खतरनाक चीनी खेल

सुरक्षा परिषद् में चीन ने आतंकी सरगना मसूद अजहर की फिर तरफदारी कर यह साबित कर दिया है कि उसे दक्षिण एशिया के अमन-चैन की कोई चिंता नहीं है. बीते एक दशक में उसने चौथी बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भावनाओं के उलट जैशे-मोहम्मद के सरगना का बचाव किया है. कभी तकनीकी कारणों का हवाला देकर और कभी ठोस सबूतों की मांग कर चीन न सिर्फ सच से परहेज कर रहा है, बल्कि वह पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर आतंकवाद को पालने-पोसने की कोशिश कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत ने बार-बार साबित किया है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकी एवं चरमपंथी गिरोहों के माध्यम से उसके विरुद्ध छद्म युद्ध का संचालन कर रही हैं. भारत को अशांत करने के लिए आतंकवाद और अलगाववाद का उपयोग पाकिस्तान की विदेश और रक्षा नीति का हिस्सा है. एक ओर दुनियाभर में भारत को समर्थन मिलता रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन हमेशा पाकिस्तान के पैरोकार की भूमिका निभा रहा है. चीन अपने देश में तो आतंकी तत्वों से बहुत कठोरता से निपटता है, पर दक्षिण एशिया में वह इनका उपयोग कर अपने आर्थिक और सामरिक हितों को साधने का प्रयास कर रहा है. चीन के झिनजियांग प्रांत में स्वायत्त क्षेत्र होने के बावजूद नागरिक अधिकारों की अवहेलना करते हुए हजारों लोगों को जेलनुमा शिविरों में रखा गया है, जहां उन्हें सरकारी विचारधारा और नीतियों की घुट्टी पिलायी जाती है. आतंकियों और अलगाववादियों को कारावास और मृत्युदंड दिया जाता है. चीनी सरकार की नीति संगठित आतंकवाद में बदलने से पहले ही कट्टरपंथ को समाप्त कर देने की है. इसके लिए वह तीन दशकों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी गिरोहों से संपर्क कर उग्यूर आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर बंद कराने और बाहरी मदद को रोकने की कोशिश करता रहा है. लगभग दो दशक पहले चीन ने आधिकारिक तौर पर तालिबान के मुखिया मुल्ला उमर से बातचीत की थी और झिनजियांग में हमले नहीं करने की शर्त पर उग्यूर आतंकियों को तालिबानियों की तरफ से लड़ने की छूट दी थी. पाकिस्तान में चीन की अनेक परियोजनाएं चल रही हैं और वहां बड़ी संख्या में चीनी कामगार भी हैं. अपने निवेश और लोगों की सुरक्षा के लिए भी वह पाकिस्तान का साथ दे रहा है. अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में हिस्सेदार बनाने की कोशिशों पर चीन का जोर भी इसी नीति का एक पहलू है. चीन के लिए मसूद अजहर कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसके मुख्य ठिकाने बहावलपुर में बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है. इस्लामिक सहयोग संगठन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे मंचों पर उसे पाकिस्तान की आवश्यकता भी है, जहां चीन की सदस्यता नहीं है. यह बेहद चिंताजनक है कि पाकिस्तान की तरह चीन भी अपने हितों को पूरा करने की कोशिश में आतंकवाद को सहयोगी बना रहा है.

चीन अपने देश में तो आतंकी तत्वों से कठोरता से निपटता है, पर दक्षिण एशिया में वह इनका उपयोग कर अपने आर्थिक और सामरिक हितों को साध रहा है.

आतंकवाद और चीन का वीटो

अविनाश गोडबोले
चीन मामलों के जानकार
avingodb@gmail.com

यह बिल्कुल अपेक्षित ही था, एक बार फिर से चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) के प्रस्ताव 1267 के तहत मसूद अजहर को प्रतिबंधित सूची में डालने पर वीटो लगा दिया है. हाल के दिनों में 'तकनीकी रोक' लगानेवाला यह चीन का चौथा वीटो है. अपने इस कदम से चीन ने भारत को यह बता दिया है कि आतंकवाद भारत की अपनी राष्ट्रीय समस्या है. साथ ही उसने यह भी जता दिया है कि 'वैश्विक आतंकवाद' और उसकी दक्षिण एशिया नीतियों में अंतर बरकरार है. यहां तक कि 41 जानें लेनेवाला आतंकी हमला भी चीन के नजरिये में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया. भारतीय चिंताओं को लेकर उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है.

इससे यह संदेश स्पष्ट है कि पाकिस्तान के साथ चीनी संबंध समुद्र से गहरा और शहद से भी मीठा है. यहां तक कि उभरती जिम्मेदार शक्ति के तौर पर प्रतिष्ठा से ज्यादा उसके लिए राष्ट्रीय हित अधिक मायने रखते हैं. कुल मिलाकर चीन एक स्वार्थी उभरती शक्ति रूप में अपनी पहचान बना चुका है.

लंबे समय से भारत इस बात को जानता है कि वैश्विक आतंकवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं. अमेरिका ने 9/11 के बाद अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच लाइन खींचने के लिए इस मुहावरे को गढ़ा था. एक बड़े व विकासशील देश के तौर पर भारत को एक पक्ष लेना था. हालांकि, वैश्विक आतंक पर हमले के नाम पर जब अमेरिका अपने वास्तविक और काल्पनिक दुश्मनों पर अफगानिस्तान और फिर इराक में कहर बरपा रहा था, तब भारत उसके समर्थन में खड़ा था. इसी दौरान अमेरिका ने सबसे महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी के तौर पर पाकिस्तान की खोज की थी. अपनी राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की नीतियों से पाकिस्तान जब भारत में आतंकवाद को जारी रखे हुए था, तब अमेरिका उसे नजरअंदाज करता रहा. इस दौरान पाकिस्तान नकदी व सामान के रूप में सहायता प्राप्त करता रहा. आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों भारत के खिलाफ हवाई हमले में पाकिस्तान ने अमेरिकी एफ-16 विमान का इस्तेमाल भी किया.

इस बार चीन है और आर्थिक मदद के रूप में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) प्रोजेक्ट है. यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना है. चीन का 62 बिलियन डॉलर का वादा पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य को नहीं बदल सकता, लेकिन यह उसके स्व-उद्देश्य के लिए एक बड़ी वजह है. सीपीईसी पाकिस्तान की उस क्षमता का उदाहरण है, जिसके माध्यम से वह ग्राहक राज्य (क्लाइंट स्टेट) बनकर महान या प्रमुख शक्ति के हितों की पूर्ति कर रहा है. चीन के लिए सीपीईसी वह नब्ज है, जिसके माध्यम से वह न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान, हिंद महासागर, ईरान और खुद के झिंजियांग प्रांत में अपने हितों को एक साथ साध रहा है. जाहिर है, चीन एक साथ अपने कई हितों को साधनेवाले देश का साथ आखिर क्यों छोड़ेगा?

किसी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने या प्रतिबंधित करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया टूट चुकी है. यह प्रमुख शक्तियों के हितों की संरक्षक भर है. भारत संयुक्त राष्ट्र से जो अपेक्षा करता है, उसे स्वयं करना होगा.

भारत किस चीज की पेशकश कर सकता है, जो पाकिस्तान की भूमिका के मुकाबले चीन को ज्यादा आकर्षक लगे, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. दिल्ली में कई लोग ऐसा मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) में उपाध्यक्ष पद के लिए भारत द्वारा चीन का समर्थन उसकी सोच में बदलाव ला सकता है. हालांकि, स्पष्ट तौर पर यह मुद्दा नहीं है. चीन को भारत से जिस सौदे की आस है, वह संभवतः यह है कि भारत बीआरआई में शामिल होने का इरादा कर ले. यद्यपि, कई आधारों पर बीआरआई के विरोध में ध्वजवाहक की अपनी स्थिति के बारे में भारत को गहराई से पता है, जो श्रीलंका, मलेशिया, युगांडा और एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों की स्थिति को देखते हुए बारंबार सही प्रतीत होता है. ऐसे में इस आधार पर किसी वादे की उम्मीद करना बेकार है.

गौरतलब है कि चीन के झिंजियांग प्रांत में बीते पांच वर्षों में आतंकवाद संबंधी ज्यादातर घटनाएं दक्षिणी झिंजियांग में ही घटी हैं, जिसकी सीमा अफगानिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है. चीन जानता है कि पाकिस्तान ही इन आतंकी घटनाओं का स्रोत है, फिर भी वह पाकिस्तान का रक्षा कवच बना हुआ है. यह कहा जाता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से परेशान देश है और इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार भी है. अब इस वीटो के बाद इस तरह के दोतरफा आतंकवाद विरोधी अभ्यासों को रोकना ही तर्कसंगत कदम होना चाहिए. अब यह स्पष्ट है कि भारत और चीन में द्विपक्षीय संबंध सामान्यतः कमजोर हुए हैं.

अब प्रश्न है कि वर्तमान परिदृश्य में भारत का विकल्प क्या होगा? यहां यथार्थवादी दृष्टिकोण से यह तर्क दिया जा सकता है कि एक बार फिर वीटो करने की चीन की नीति जैश-ए-मोहम्मद के बालाकोट शिविर पर भारत द्वारा किये गये एहतियातन हमले को न्यायोचित ठहराता है. भारतीय दृष्टिकोण से, वैश्विक प्रणाली आज की तारीख में अराजकता का प्रतिनिधित्व करती है. किसी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने या प्रतिबंधित करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया टूट चुकी है. यह प्रमुख शक्तियों के हितों की संरक्षक भर है. भारत संयुक्त राष्ट्र से जो अपेक्षा करता है, उसे स्वयं करना होगा. सीमा पार से जिस आतंकवाद की समस्या का वह सामना करता है, उसे खत्म करने के लिए वह जो उपाय कर रहा है, वह सही है, लेकिन इसे लेकर भारत को व्यावहारिक होना होगा. भारत की बदले की प्रतिक्रिया, भारत के लिए उपलब्ध विकल्पों का नतीजा है.

दूसरे स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में अपने राष्ट्रीय उद्देश्य हेतु शामिल होने के लिए भारत के अथक प्रयास से भी यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत दक्षिण एशिया में चीन की शक्ति को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मान्यता देता है. अगर ऐसा है, तो इसे आगे बीजिंग के साथ कूटनीतिक उपायों के जरिये अपने तरीके से काम करना होगा. वहीं दूसरी ओर, अगर भारत का इरादा केवल इस आधार पर चीन को घेरना है कि वह 'एक जिम्मेदार उभरती शक्ति' की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, तो वह भी पर्याप्त नहीं है. चीन कभी भी पाकिस्तान के सामने असहज नहीं होने जा रहा है. भारत को अराजकता को पहचानने और खुद के बूते अपने राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने की जरूरत है.

देश में देशभक्ति की वापसी

तरुण विजय
वरिष्ठ नेता, भाजपा
tarunvijay55555@gmail.com

ऐसा कभी हुआ नहीं कि भारतीय वायुसेना अधिकृत ट्विटर पर अपने वायुवीर अभिनंदन वर्तमान की प्रशस्ति में लिखी कविता प्रसारित की हो. देश के मीडिया ने उसे मान्य किया, उसकी खबर छापी. यूं तो हमारे देश में देशभक्ति का जज्बा हमेशा विद्यमान रहा ही है. पर यह भी कटु सत्य है कि सामान्यतः दरबार में हाजिरी लगानेवाले रायबहादुर और रायसाहब लोग ऐश और विलास करते रहे, जबकि भगत सिंह फांसी पर चढ़ते रहे.

आज माहौल बदला हुआ है. देशभक्ति सिर्फ सीमा की रक्षा में प्राण देना मात्र नहीं, दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी अड्डे तबाह करना मात्र नहीं, बल्कि मीडिया के अवतारों में राष्ट्रीय विश्वास पर हो रहे हमलों का करारा जवाब देना भी है. पहली बार सेकुलर कहे जानेवाले उस वर्ग को मुंह छुपाये रक्षात्मक होना पड़ रहा है, जो सात दशकों से देश के बौद्धिक आकाश में एकछत्र राज और प्रभुत्व जमाये हुए था.

देश की बहुसंख्यक जनता हिंदू है- इसी कारण कुछ लोगों को सभी मतों, संप्रदायों को समान अधिकार, अवसर और हिंदुओं पर क्रुद्ध होने, उनका मजाक उड़ाने के भी अधिकार प्राप्त हैं. पूरे देश में दो लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान छात्र-छात्राएं या तो गृह मंत्रालय से छात्रवृत्ति पाकर या अपने खर्च पर पढ़ने के लिए देश के विभिन्न नगरों में जाते हैं और इनमें शाल, कश्मीरी हस्तकला के व्यापारी, निजी व सरकारी दूरदर्शन मीडिया में कार्यरत कश्मीरी संवाददाता भी शामिल हैं. एक दुर्भाग्यजनक घटना लखनऊ में होती है, तो उसे सेकुलर मीडिया 'कश्मीरियों पर हमला' कहकर पूरे देश पर थोप देता है. लेकिन, पूरे देश में कश्मीरी सुरक्षित और निर्भय काम करते आ रहे हैं- इनकी कोई चर्चा नहीं होती. मैं स्वयं देहरादून में कश्मीरी मुस्लिम छात्राओं से मिला था, उन्हें उस वक्त पुलिस ने हर सुरक्षा दी थी.

राफेल विमानों का मामला ऐसा ही एक अन्य उदाहरण है. वे सब जो विभिन्न आर्थिक अपराधों, घोटालों में अभियुक्त बने हैं या अदालती और जांच एजेंसियों के घेरे में हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखायी, आज क्यों लामबंद हो गये? अपुष्ट आधार पर शक पैदा कर वे भारतीय सैन्य बल का मनोबल बढ़ा रहे हैं या भारत के शत्रुओं का? पर आम तौर पर उन्हें जो शाब्दिक प्रहार झेलने पड़े, इसके वे आदी नहीं थे.

हिंदुओं को अपमानित कर देश वैसे ही नहीं चलाया जा सकता, जैसे किसी भी जाति या मतावलंबी को तिरस्कृत कर संविधान बचाया नहीं जा सकता. विभिन्न दलों व क्षेत्रों में हिंदू मानस भारत की शक्ति है, कमजोरी नहीं. पर आज तक हिंदू संवेदनाओं का अपमान प्रगतिशील का मानक बना हुआ था. अब खबरें बनती हैं कि पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने कुंभ में डुबकी लगायी या काशी विश्वनाथ धाम का भूमि पूजन किया. अमेरिकी जनता को पता चलता है कि भारत से एक ऐसा प्रधानमंत्री भी आया है, जो व्हॉइट हाउस के शानदार डिनर में नवरात्रों का व्रत होने के कारण केवल पानी पीता रहा और न्यूयार्क, लंदन, जेद्दाह, दुबई से शंघाई तक भारत की भाषा में बोलता रहा.

जिन कश्मीरी मुसलमानों ने वहां के हिंदुओं को निकाले जाने के समय सन्नाटा ओढ़े रखा, वे आशा करते हैं कि शेष देश में हिंदू उनके साथ प्रेम और आत्मीयता का व्यवहार करेंगे. वैसा तो होता ही है. पर क्या आज तक एक भी कश्मीरी मुस्लिम या दिल्ली के सेकुलर पत्रकार ने पांच लाख हिंदुओं के कश्मीर से बर्बरतापूर्वक किये गये निष्क्रमण का विरोध किया और मुस्लिम जेहादियों को कठघरे में खड़ा किया?

देशभक्ति अब हिंदू उदय के साथ जुड़कर अधिक प्रभविष्णुता पा गयी है. संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्र में हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई के नारे का धरातल पर सच होना केवल तब तक संभव है, जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं. जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होने की तरफ मुड़ गया, भारत अभारत हो जायेगा. यह कहना, सुनना बेतुका बतानेवाले कभी भी वर्ष 1947 के नरसंहार, मीरपुर और बहावलपुर में हिंदुओं पर हुए हमलों की पाशविकता का स्मरण नहीं करना चाहते. वे सब ओर धनाढ्य सुरक्षित बिलों में वैसे ही सुरक्षित हैं, जैसे अंग्रेजों के जमाने में रायसाहब हुआ करते थे.

पिछले दिनों देश के एक वरिष्ठ राजदूत के साथ सायंकालीन रिसेप्शन में बातें हुईं. वे बोले- 'पहली बार भारत के प्रति देखने का वैश्विक नजरिया बदला है. एक ऐसा क्षण था, जब पोखरण-2 हुआ, पर पाकिस्तान के भीतर घुसकर हजार-हजार किलो के बम गिराकर लौट आना, यह भारत के लिए अविश्वसनीय है. क्योंकि अब तक भारत एक दब्बू, युद्ध के बाद भी हानिकारक समझौते करनेवाला, भ्रष्ट और विलासी राजनेताओं का देश माना जाता रहा.

देशभक्ति भारत का धर्म है. यहां गुरु तेगबहादुर साहब 'हिंद की चादर' कहे गये- सिखों या पंजाब की नहीं. शिवाजी के नाम पर तमिलनाडु में लोग अपना नाम रखते हैं. विवेकानंद जब धर्म पर बोलते हैं, तो भारत उसमें हर वाक्य में अभिव्यक्त होता है. लोग गर्व से अपने बच्चों का नाम भारत रखते हैं. यह किसी अन्य देश में नहीं होता.

देशभक्ति अब लोकतंत्र के वर्तमान उत्सव का भी मुख्य बिंदु बनी है, तो यह शुभ है. पहली बार देश में हर नेता (हर दल से) स्वयं को बेहतर हिंदू, बेहतर देशभक्त बता रहा है. जय हो!

देशभक्ति अब लोकतंत्र के वर्तमान उत्सव का भी मुख्य बिंदु बनी है, तो यह शुभ है. पहली बार देश में हर राजनेता- हर दल से- स्वयं को बेहतर हिंदू, बेहतर देशभक्त बता रहा है.

बोधि वृक्ष

विज्ञान और धर्म

सच्चा विज्ञान हमें सावधान रहना सिखाता है. जिस तरह पुरोहितों से हमें सावधान रहना चाहिए, उसी तरह वैज्ञानिकों से भी हमें सावधान रहना चाहिए. पहले अविश्वास से आरंभ करो. छानबीन करो, परीक्षा करो और प्रत्येक वस्तु का प्रमाण मांगने के बाद उसे स्वीकार करो. आजकल के विज्ञान के बहुत से प्रचलित सिद्धांत, जिनमें हम विश्वास करते हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं. विज्ञान एकत्व की खोज के सिवा और कुछ नहीं है. ज्यों ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जायेगा, त्यों ही उसकी प्रगति रुक जायेगी, क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा. इसका उदाहरण यह है- रसायन-शास्त्र यदि एक बार उस एक मूल तत्व का पता लगा ले, जिससे और सब द्रव्य बन सकते हैं, तो फिर वह अपने और आगे नहीं बढ़ सकेगा. भौतिक-शास्त्र जब उस शक्ति का पता लगा लेगा- अन्य शक्तियां जिसकी अभिव्यक्ति हैं, तब वह वहीं रुक जायेगा. ठीक वैसे ही धर्म-शास्त्र भी उस समय पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, जब वह उसको खोज लेगा, जो एकमात्र परमात्मा है, अन्य सब आत्माएं जिसकी प्रतीयमान अभिव्यक्तियां हैं. इस प्रकार अनेकता और द्वैत में होते हुए इस परम अद्वैत की प्राप्ति होती है. धर्म इससे आगे नहीं जा सकता. यही समस्त विज्ञानों का चरम लक्ष्य है. गणित जैसे शास्त्र में भी बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं, जो केवल कामचलाऊ परिकल्पना के सदृश ही हैं. जब ज्ञान की वृद्धि होगी, तो ये फेंक दिये जायेंगे. ज्ञान का मार्ग अच्छा है, परंतु उसके शुष्क वाद-विवाद में परिणत हो जाने का डर रहता है. भक्ति बड़ी ही उच्च चीज है, पर उसके निरर्थक भावुकता पैदा होने के कारण वास्तविक चीज ही के नष्ट हो जाने की संभावना रहती है. ज्ञान की दृष्टि में भक्ति मुक्ति का एक साधन भी है और साध्य भी. मेरी दृष्टि में तो यह भेद नाममात्र का है- ज्ञानी और भक्त दोनों ही अपनी-अपनी साधना-प्रणाली पर विशेष जोर देते हैं; वे यह भूल जाते हैं कि पूर्ण भक्ति के उदित होने से पूर्ण ज्ञान बिना मांगे ही मिल जाता है और इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान के साथ पूर्ण भक्ति भी अभिन्न है.

स्वामी विवेकानंद

आपके पत्र

फिर आतंकवाद से हारी दुनिया

चीन ने एक बार फिर अपने वीटो शक्ति का उपयोग कर जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा लिया. वीटो की शक्ति सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों के पास है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रेजॉल्यूशन 1267 के तहत मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन चीन के वीटो की वजह से यह पास नहीं हो सका. अगर अजहर वैश्विक आतंकी घोषित हो जाता, तो पाकिस्तान को उसकी सारी संपत्ति जब्त करनी पड़ती और उसकी आवाजाही पर बैन लगाना पड़ता. चीन पाकिस्तान को खुश करने में लगा है क्योंकि चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर चीन की महत्वाकांक्षी योजना है. वक्त है विश्व के हर देश आतंकवाद के खिलाफ विरोध करे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में बदलाव लाने की पहल करे .

सोनल कुमार महतो, टालीगंज, कोलकाता

राजनीतिज्ञों की अदूरदर्शिता

अगर कोई मनुष्य सोया हुआ है, तो उसे आसानी से जगाया जा सकता है, परंतु जो मनुष्य सोने का उपक्रम कर रहा है, उसे जगाना असंभव है. भारत की राजनीति भी कुछ इसी तरह की हो गयी है. पुलवामा अटैक के बाद हुए एयर स्ट्राइक पर देश के कुछ लोग इस पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं. ये सारे संभ्रांत लोग राजनीतिक दल से हैं. ऐसे लोग आरंभ से ही मान कर चलते हैं कि, उन्हें खुलकर विरोध करना है, चाहे विषय कितना भी गंभीर क्यों न हो. ऐसे लोग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर अपनी बेबाक राय दे आते हैं. उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उनके आचरण से दुश्मनों के हौसले बुलंद हो जाते हैं. आज कुछ नेताओं में आपसी सामंजस्य का अभाव है, जिससे देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचता है. राजनीतिज्ञों को आपस में मिलकर सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए ताकि देश प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर सके और साथ ही साथ देश की सुरक्षा और अखंडता के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे देश के दुश्मनों के हौशले बुलंद हो.

स्नेहा चौधरी, करणीबाग, देवघर

पहले मन का प्रदूषण खत्म करें

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के लिए पटाखों से ज्यादा जिम्मेवार वाहनों को बताया है. यह बिलकुल सही बात है. उसने केंद्र सरकार से पटाखों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के तुलनात्मक अध्ययन के विषय में भी पूछा है. पटाखों का उपयोग तो हम कभी-कभी ही करते है, पर वाहनों का उपयोग तो हर दिन करते है. छोटी -छोटी बातें बड़ा फर्क डालती है, और यही बात प्रदूषण से निबटने के बारे में भी लागू होती है. हमारी मानसिकता ही प्रदूषित हो गयी है. प्रदूषण से निबटने का जिम्मा सरकार पर थोप देते हैं और इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते. सब अपनी सुविधा देखते है, चाहे उससे प्रदूषण ही क्यों न होता हो. इसलिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हम सभी को चाहिए कि अपने मन के प्रदूषण को खत्म करें.

सीमा साही, बोकारो

कुछ अलग

सामाजिकता और शिक्षा व्यवस्था

सन्नी कुमार
टिप्पणीकार
sunnyand65@gmail.com

यह परीक्षाओं का समय है. कुछ बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, तो कुछ की होनेवाली हैं. इसके बाद आयेगा परीक्षा परिणाम का दौर और उससे जुड़ी तमाम आकांक्षाओं के बनने-बिगड़ने का समय. विरोधाभास यह है कि एक तरफ आजकल बहुतायत में विद्यार्थियों को 95 से 100 फीसदी के बीच अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि ये बच्चे देश-काल की जमीनी हकीकत से बहुत कम वाकिफ होते हैं. आखिर ऐसा क्यों है? आखिर शिक्षण प्रणाली का सामाजिकता से कट जाने के पीछे क्या वजहें हैं? इसकी दो मुख्य वजहें हैं, जो एक-दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं. पहला, पूरी शिक्षण प्रणाली का 'स्कूल' जैसे औपचारिक संस्थान तक सिमट जाना और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा कारण इस स्कूली शिक्षा का एक ऐसे पाठ्यक्रम पर आश्रित होना, जो अपनी क्षमता पर स्थानीयता और सामाजिकता से कटा हुआ है.

उदारवादी जीवन शैली का प्रभुत्व स्थापित होने के साथ ही एकल परिवार का चलन बढ़ा और इस प्रकार बचपन के 'सामुदायिक जीवन' का दायरा सीमित होता गया. नौकरीपेशा अभिभावक, छोटा परिवार और गिनती के पड़ोसी के कारण बच्चों का समाजीकरण भी इस छोटे दायरे में ही विकसित होने लगा. सामाजिक जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव तथा विभिन्न आयुवर्ग, लिंग, और अलग पृष्ठभूमि के व्यक्तियों से परस्पर संवाद की कमी से बच्चों का अपनी दुनिया से स्वाभाविक जुड़ाव बाधित हो गया. इस कमी की पूर्ति का पूरा भार स्कूल पर डाल दिया गया. समाज ने अपने बच्चों की सामाजिक परवरिश का लगभग संपूर्ण हिस्सा स्कूल और ट्यूशन को सौंप दिया, जो अपनी अंतर्निहित संरचनात्मक दोष के कारण इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे.

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में निर्धारित पाठ्यक्रम और उस पर आधारित परीक्षा जहां स्कूली बच्चों में अधिक से अधिक सीखने की प्रवृत्ति को बाधित करती है, वहीं स्कूली चारदीवारी बच्चों को प्रत्यक्ष सामाजिक अनुभव से वंचित करते हैं. इस प्रकार पूरी शिक्षा का मूल्यांकन तय पाठ्यक्रम को तैयार करने और इस आधार पर होनेवाली परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर केंद्रित हो जाता है. बच्चे, शिक्षक और अभिभावक सभी इस बात के लिए मेहनत करते हैं कि उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हो जायें, न कि इस पर कि शिक्षा बच्चों को जिज्ञासु और नवाचारी बनाये. एक समय के बाद यह शिक्षा अर्थव्यवस्था से लेकर जीवन के विविध क्षेत्रों के लिए बेहद अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है.

इस दोषपूर्ण प्रक्रिया को पाठ्यक्रम का स्वरूप और सघन कर देता है. दरअसल, इस तरह का पाठ्यक्रम हमारे बच्चों को देश की चुनिंदा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो तैयार कर सकता है, लेकिन इसकी सार्वभौमिकता बच्चों को निश्चित ही अपनी स्थानीयता से काट देता है. एकदम सूखे प्रदेश में रहनेवाले बच्चों को बाढ़ नियंत्रण की विधियां समझाकर हमारी शिक्षा व्यवस्था किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है, इस पर एक बार फिर से हमें विचार करने की जरूरत है.

देश दुनिया से

शांति बहाली से बड़ा कोई विकल्प ही नहीं

अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव कुछ थम गया है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या नुकसान उठाया है. अमन और शांति की बात को बेकार नहीं माना जाना चाहिए. अमन तभी कायम होगा, जब हम योजना बनाकर इस पर काम करें. दक्षिण एशिया में दो पड़ोसी देश जब इस तरह आपस में तनाव पालेंगे, तब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस बात का डर सतायेगा कि कहीं इनमें परमाणु संघर्ष न छिड़ जाये. हम जानते हैं कि DAWN परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के परिणाम क्या हैं और इससे देशों को आम लोगों की जान को कितना बड़ा खतरा है. इन खतरों को अनदेखा नहीं किया जा सकता. परमाणु हथियारों की क्षमता को बढ़ानेवाले देशों की जिम्मेदारी यह भी है कि वे अमन और शांति को कायम रखने की शर्त को प्राथमिकता दें. पूरी दुनिया में यह तथ्य सर्वविदित है कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं बन सका है, बल्कि इसने संकटों को और भी बढ़ा दिया है. हालांकि, दोनों देशों को यह बात मालूम है कि युद्ध उनके लिए कितना महंगा पड़ सकता है, और यही वह बात है, जो किसी अन्य तथ्य के मुकाबले युद्ध के खिलाफ भी जाती है. दुर्भाग्य है कि दोनों तरफ का मीडिया एक खतरनाक कौमपरस्ती को बढ़ावा दे रहा है.

आईए रहमान

कार्टून कोना

ईरान में न्याय

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है